तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीन देशों के साथ हुए समझौतों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक : डिजिटल क्षेत्र में निवेश को तेजी से मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्मेनिया, एंटीगुआ और बारबुडा तथा सिएरा लियोन के साथ डिजिटल समाधानों को साझा करने और तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए अलग-अलग समझौता ज्ञापनों को स्वीकृति प्रदान की है। आर्मेनिया और सिएरा लियोन के साथ इस साल 12 जून और एंटीगुआ और बारबुडा के साथ 13 जून को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौते तीन साल के लिए प्रभावी होंगे।

दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्षेत्र में सहायता और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ा कर कई देशों और संबंधित एजेंसियों के साथ तत्परता से जुड़ रहा है। इस पहल के पीछे भारत सरकार की एक व्यापक सोच है। इसका मकसद डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सरीखी सरकार के प्रयासों की मदद से देश को प्रौद्योगिकी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और अन्य देशों के साथ श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करके डिजिटल के क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यावसायिक अवसरों और निवेश को बढ़ाना है। ब्यूरो

सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान मकसद

समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य द्विपक्षीय डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों (जैसे इंडिया स्टैक) और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के क्षेत्र में द्विपक्षीय जी2जी और बी2बी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। समझौतों में व्यवस्था के संचालन के लिए भी एक मुश्त कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पीएम मोदी के व्यापक दृष्टिकोण ने जी-20 को बनाया सफल

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'विषय के विभिन्न पहलुओं को स्थापित करने में पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। प्रस्ताव में कहा गया कि पीएम के जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने जी-20 कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया। 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें जी-20 आयोजनों के एक अभूतपूर्व आयोजन को दर्शाती हैं।

पूरे देश को होगा फायदा

प्रस्ताव में कहा गया कि जी-20 के प्रमुख परिणामों का लाभ पूरे देश को होगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल के अवसर मिलेंगे।